पाकिस्तान द्वारा सीमा पर कवच कोठरियों (पिल बाक्स) का निर्माण

*734. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पु... कसूर के नाले के साथ-साथ वैसी कवच कोठरियां (पिल बाक्स) बनाई हैं, जैसी उसने इच्छोगिल नहर के साथ-साथ बनाई थीं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पाकिस्तान हमारी सीमाओं के उस पार सैनिक कार्यों का निर्माण कर रहा है, और पिल बाक्स बना रहा है।

(ख) इन सभी अभिवृद्धियों को अपनी रक्षा आयोजनाओं में ध्यान रखा जाता है।

Management of Ordnance Factories

*735. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of Ordnance Factories and units which are headed by experienced technical military personnel and the number of such factories headed by civil servants; and

(b) whether it is proposed to place all the factories under the charge of experienced technical military personnel and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) All the ordnance factories under the Ministry of Defence are headed by technically trained civilians.

(b) No, Sir. There is no such proposal under examination as there is already a regular service known as the Indian Ordnance Factories Service for manning the various posts in Ordnance Factories.

काठमांडू-कोदारी सड़क

*736. श्री हु० राम :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री आत्म दास :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय लोगों को चीन द्वारा बनाई गई काठमांडू-कोदारी सड़क का प्रयोग करने से मना कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के अधिकारियों को इस प्रकार उस सड़क का प्रयोग करने से मना नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). उस समय जो सूचना सुलभ थी, उसके आधार पर 13 जून, 1967 को राज्य सभा में ऐसे ही एक सवाल के जवाब में यह स्पष्ट किया गया था कि भारतीयों को नेपाल में चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू—कोदारी सड़क पर मुक्त रूप से आने-जाने दिया जाता था। तब यह बताया गया था कि नेपाल सरकार ने वह सड़क आम जनता के लिए 2 जून, 1967 को खोली थी और तब से ही भारतीय लोग कोई परमिट लिए बगैर मुक्त रूप से आ-जा सकते थे और भारतीयों

के अलावा अन्य विदेशियों को उस पर आने-जाने के लिए परमिट लेने पड़ते थे। यह सूचना हमारे राजदूतावास से प्राप्त इस सूचना पर आधारित थी कि "2 जून को नेपाल के महामहिम की सरकार ने अधिकृत रूप से यह सूचना दी थी कि सड़क आम जनता के लिए खोल दी गई है। यह भी बताया गया था कि भारतीयों को छोड़ कर तमाम विदेशी लोगों को सड़क पर आने-जाने के लिए वीजा (परमिट) लेने होंगे। भारतीयों और नेपालियों को किसी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं है।" उसके बाद कई भारतीय लोग कोई परमिट लिए बगैर सड़क पर आए-गए।

लेकिन 23 जून को सवेरे नेपाल के विदेश मन्त्रालय ने हमारे राजदूतावास को जबानी तौर पर बताया कि सभी गैर-नेपालियों को, जिनमें भारतीय शामिल हैं, काठमांडू-कोडारी सड़क पर बारा बीसे से आगे जाने के लिए परमिट लेने होंगे क्योंकि वह इलाका नेपाल-चीन सीमा से 20 किलोमीटर के अन्दर होने के कारण निषिद्ध क्षेत्र है।

इस घटना से सरकार को आश्चर्य हुआ है क्योंकि वह यह आशा नहीं करती थी कि नेपाल में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को नेपाल में निषिद्ध-क्षेत्रों सहित भीतर के किसी स्थान पर मुक्त रूप से आने-जाने के उद्देश्य से अन्य विदेशियों के साथ वर्गीकृत कर दिया जायगा। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशी (निषिद्ध क्षेत्र) आदेश 1963 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भी नेपाली राष्ट्रिकों के लिए खास सांविधिक छूट देने की व्यवस्था है जिसमें उन्हें इस देश के 'संरक्षित' और 'निषिद्ध' क्षेत्रों में आने-जाने की स्वतन्त्रता है। हम महामहिम की सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह नेपाल में 'निषिद्ध' क्षेत्रों को लेकर अपने विनियमों की व्यवस्थाओं पर फिर विचार करें जिससे कि पारस्परिकता के आधार पर नेपाल में भारतीय राष्ट्रिक, 1950 की शांति एवं मैत्री की संधि की व्यवस्थाओं के अनुसार, नेपाली राष्ट्रिकों के साथ समान अधिकार प्राप्त कर सकें।

27 मई, 1967 को चीनियों ने नेपाल-चीन सीमा के तिब्बत की ओर नेपाल के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अखबार वालों को तथा पाकिस्तान के राजदूत को लंच पर आमन्त्रित किया था। जनसाधारण के लिए सड़क खोलने से पहले ऐसा उद्घाटन विशेष परिस्थितियों में किया गया था।

जैसा कि पहले कहा गया है, सरकार की आशा है कि नेपाल में काठमांडू-कोडारी तथा अन्य सड़कों पर आने-जाने के मामले में भारतीय राष्ट्रिकों को नेपाली राष्ट्रिकों के साथ ही समान अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि 1950 की भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि में व्यवस्थित है।

Relations with Indonesia

*737. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether there has been any further improvement of diplomatic and trade relations with Indonesia recently; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). Our diplomatic and trade relations with Indonesia are developing well and, in general, the Indonesian attitude continues to be friendly. The Foreign Minister visited Djakarta in January and discussed various questions of mutual interest and concern. In the commercial field, trade is reviving. A trade agreement with Indonesia was signed last year and a credit of Rs. 10 crores was also granted. Letters of credit to the extent of about 2/5th of this amount have so far been approved by the Indonesian authorities.